

सोशल मीडिया और भारत में डिजिटल सक्रियता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. शाहेदा बानो सिद्दीकी

Author Affiliation:

सह प्राध्यापक (समाजशास्त्र), शासकीय टी. आर. एस. महाविद्यालय, रीवा, म प्र

Citation of Article: सिद्दीकी, शाहेदा बानो. (2025). सोशल मीडिया और भारत में डिजिटल सक्रियता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. International Journal of Classified Research Techniques & Advances (IJCRTA) ISSN: 2583- 1801, 5 (1), pg. 49-54. ijcrt.org

DOI: 10.5281/zenodo.15476084

सारांश:

यह शोध पत्र भारत में डिजिटल सक्रियता की प्रवृत्तियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने जनसंगठनों के स्वरूप, संगठन और संदेश प्रसार की विधियों को बदला है। साथ ही यह भी समझा जाएगा कि डिजिटल सक्रियता ने सामाजिक परिवर्तन में किस हद तक योगदान दिया है।

परिचय:

21वीं शताब्दी का प्रारंभ डिजिटल तकनीक के तीव्र विकास और संचार माध्यमों के अभूतपूर्व विस्तार का साक्षी रहा है। विशेषतः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म — जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि — ने सामाजिक संवाद, विचार-विनिमय और सामूहिक क्रियाशीलता के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। भारत, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है और जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा है, वहां सोशल मीडिया सामाजिक सक्रियता का एक सशक्त मंच बनकर उभरा है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली डिजिटल सक्रियता सामाजिक संरचनाओं, शक्ति समीकरणों, वर्ग, जाति और लैंगिक संबंधों पर भी प्रभाव डालती है। यह पारंपरिक मीडिया के केंद्रीकृत प्रभाव को चुनौती देते हुए एक बहुकेन्द्रीय संवाद प्रणाली का निर्माण करती है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवाज़ उठा सकता है और वैश्विक विमर्श का हिस्सा बन सकता है। परंपरागत सामाजिक आंदोलनों में जहाँ संगठन, संवाद और लामबंदी की प्रक्रिया धीमी और भौगोलिक रूप से सीमित थी, वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने इन प्रक्रियाओं को तीव्र गति प्रदान की है। सोशल मीडिया अब न केवल सूचना प्रसार का माध्यम है, बल्कि यह विरोध, समर्थन, संगठन निर्माण और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है।

भारत में सोशल मीडिया की पहुँच और उपयोगिता:

भारत में डिजिटल क्रांति ने बीते दो दशकों में सूचना और संचार की दुनिया में एक अद्वितीय परिवर्तन लाया है। इंटरनेट की सुलभता, मोबाइल तकनीक में क्रांतिकारी विकास, और सस्ते डेटा प्लान्स के चलते भारत विश्व का सबसे बड़ा सोशल मीडिया उपभोक्ता देश बन चुका है। आज ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रसार देखा जा सकता है, जिसने न केवल संवाद की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ा है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को भी एक नई दिशा प्रदान की है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) और विभिन्न अनुसंधानों के अनुसार, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2023 तक 85 करोड़ से अधिक हो चुकी थी, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया का सक्रिय उपयोगकर्ता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और हाल ही में उभरे प्लेटफॉर्म जैसे कू ऐप (Koo) और शेयरचैट (ShareChat) जैसे स्वदेशी विकल्प भी भारतीय उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। ग्रामीण भारत में भी इंटरनेट और सोशल मीडिया की पहुंच तेजी से बढ़ रही है, जहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए इन माध्यमों का उपयोग हो रहा है। स्मार्टफोन की उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता अभियानों ने इस विस्तार को और भी सुलभ बनाया है।

भारत में सोशल मीडिया का उपयोग केवल व्यक्तिगत संवाद और मनोरंजन तक सीमित नहीं है; बल्कि यह सामाजिक सक्रियता, राजनीतिक विमर्श, उपभोक्ता जागरूकता, आपदा प्रबंधन, शैक्षिक उद्देश्यों, और व्यवसायिक नेटवर्किंग जैसे विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनेक सामाजिक मुद्दों — जैसे लैंगिक समानता, जातीय भेदभाव, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार — पर जागरूकता फैलाने और जन समर्थन जुटाने के लिए सोशल मीडिया एक प्रमुख मंच बन चुका है। राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन सोशल मीडिया का उपयोग नीतियों के प्रचार, चुनाव अभियानों, और जनमत निर्माण के लिए कर रहे हैं। 2014 और 2019 के आम चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका ने स्पष्ट रूप से इसकी शक्ति को रेखांकित किया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने राहत कार्यों के समन्वय, आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान, और सहायता जुटाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से, सोशल मीडिया ने भारत में सामाजिक वर्गों, जातियों और आयु समूहों के बीच संवाद के नए पुल बनाए हैं। यह एक लोकतांत्रिक मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ पारंपरिक बाधाओं को लांघते हुए व्यक्तियों और समुदायों को अपनी आवाज उठाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

डिजिटल सक्रियता का स्वरूप तथा कुछ प्रमुख उदाहरण:

भारत में डिजिटल सक्रियता का स्वरूप बहुआयामी और गतिशील है। सोशल मीडिया ने सामाजिक आंदोलनों को एक नया जीवन प्रदान किया है, जहाँ जनक्रोश, समर्थन, और विरोध अभिव्यक्त करने के पारंपरिक साधनों के साथ-साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म का भी व्यापक उपयोग होने लगा है। डिजिटल सक्रियता के माध्यम से सूचना का त्वरित प्रसार, जनमत निर्माण, और समर्थन जुटाने की प्रक्रियाएं अत्यंत तीव्र और व्यापक हो गई हैं। इससे आंदोलनों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक पहचान भी प्राप्त होती है।

निर्भया कांड (2012) के पश्चात उभरे जन आंदोलन ने भारत में डिजिटल सक्रियता के प्रभाव को पहली बार व्यापक स्तर पर रेखांकित किया। सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियानों ने सरकार को कड़े कानून बनाने और

बलात्कार विरोधी उपायों को मजबूत करने के लिए बाध्य किया। इसी प्रकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में सोशल मीडिया पर "#NoCAA" और "#ShaheenBaghProtests" जैसे हैशटैग अभियानों ने देशभर में नागरिक अधिकारों को लेकर व्यापक संवाद प्रारंभ किया। किसानों के आंदोलन (2020-21) में भी सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई, जहाँ किसानों ने अपनी माँगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब का सक्रिय उपयोग किया।

#MeToo आंदोलन ने लैंगिक असमानता और कार्यस्थलों पर यौन शोषण जैसे संवेदनशील मुद्दों को उजागर करने में डिजिटल सक्रियता की शक्ति को दर्शाया। हजारों महिलाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए, जिससे समाज में एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई और कई संस्थानों को अपने आंतरिक तंत्रों की समीक्षा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों — जैसे #SaveAarey और #FridaysForFuture — ने भी युवा वर्ग को संगठित करने और नीति निर्माताओं पर दबाव बनाने में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमाणित किया।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भारत में डिजिटल सक्रियता ने पारंपरिक आंदोलनों की सीमाओं को तोड़ते हुए सामाजिक चेतना के नए स्वरूपों को जन्म दिया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन समूहों को भी एक मंच प्रदान किया है, जो पारंपरिक मीडिया या राजनीतिक ढाँचे में अक्सर उपेक्षित रह जाते थे। यद्यपि यह सक्रियता कई बार सतही समर्थन (Slacktivism) तक सीमित रह जाती है, फिर भी इसकी भूमिका को समकालीन सामाजिक आंदोलनों के स्वरूप और प्रभावशीलता में एक निर्णायक कारक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

संगठन और संदेश प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका:

सोशल मीडिया ने संगठन और संदेश प्रसार के पारंपरिक ढाँचों को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहाँ सामाजिक आंदोलनों के लिए भौतिक सभाओं, पर्चों, और पारंपरिक मीडिया जैसे साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म — जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और यूट्यूब — के माध्यम से आंदोलन की योजना बनाना, समर्थकों को संगठित करना, और संदेश प्रसारित करना अत्यंत सरल, त्वरित और प्रभावी हो गया है। डिजिटल मंचों ने विभिन्न सामाजिक समूहों और आंदोलनों को सीमाओं से परे एकजुट करने का अवसर प्रदान किया है, जिससे भौगोलिक दूरी और संसाधनों की कमी जैसी बाधाएँ काफी हद तक समाप्त हो गई हैं।

सोशल मीडिया के माध्यम से संगठनकर्ता रियल-टाइम में सूचनाएँ साझा कर सकते हैं, कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर सकते हैं, और आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हैशटैग अभियानों, लाइव स्ट्रीमिंग, और वर्चुअल सभाओं के ज़रिए आंदोलन की अपील को व्यापक बनाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, किसानों के आंदोलन के दौरान ट्विटर पर "#FarmersProtest" अभियान ने लाखों लोगों को आंदोलन से जोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन हासिल किया। इसी प्रकार, निर्भया आंदोलन में फेसबुक पेजों और ट्विटर अभियानों के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क स्थापित किया गया, जिसने सरकार पर त्वरित कार्रवाई करने का दबाव डाला।

मूल रूप से सोशल मीडिया न केवल सूचना साझा करने का माध्यम है, बल्कि एक गतिशील संगठनात्मक औजार भी बन चुका है, जो विचारों, अनुभवों और भावनाओं को जोड़कर एक सामूहिक चेतना का निर्माण करता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने सत्ता और सूचना के केंद्रीकरण को चुनौती दी है और व्यक्तिगत आवाजों को सामूहिक शक्ति में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान की है। यद्यपि गलत सूचना और डिजिटल विभाजन जैसी समस्याएँ इसके प्रभाव को जटिल बनाती हैं, फिर भी आज के सामाजिक आंदोलनों में संगठन और संदेश प्रसार के क्षेत्र में सोशल मीडिया की भूमिका को निर्णायक माना जा सकता है।

डिजिटल सक्रियता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण:

डिजिटल सक्रियता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण यह दिखाता है कि कैसे तकनीकी नवाचारों ने सामाजिक संरचनाओं, सत्ता समीकरणों और सामूहिक चेतना को प्रभावित किया है। पारंपरिक सामाजिक आंदोलनों की तुलना में डिजिटल सक्रियता ने संवाद के लोकतांत्रिक रूपों को सशक्त बनाया है, जहाँ हर व्यक्ति अपने विचार, अनुभव और असहमति को व्यापक समुदाय तक पहुँचा सकता है। यह प्रक्रिया उन सामाजिक समूहों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है, जो मुख्यधारा के राजनीतिक और मीडिया तंत्र में लंबे समय तक उपेक्षित रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से हाशिए पर पड़े समुदायों को न केवल अपनी पहचान स्थापित करने का अवसर मिला, बल्कि सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, जातीय भेदभाव, और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों पर नई जागरूकता भी उत्पन्न हुई।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से डिजिटल सक्रियता सामाजिक नेटवर्क सिद्धांत (Social Network Theory) के अनुरूप कार्य करती है, जहाँ नेटवर्क में जुड़े व्यक्ति सूचनाओं और विचारों का तीव्र प्रसार करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत (Symbolic Interactionism) यह दर्शाता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतीकों, हैशटैग, और छवियों के माध्यम से आंदोलनों का अर्थ गढ़ा जाता है और सामूहिक पहचान निर्मित होती है। फिर भी, यह भी महत्वपूर्ण है कि डिजिटल सक्रियता अक्सर "स्लैक्टिविज्म" (slacktivism) का रूप ले लेती है, जहाँ लोग वास्तविक सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता के बजाय केवल सतही समर्थन तक सीमित रहते हैं।

डिजिटल सक्रियता ने सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) और सामाजिक परिवर्तन (Social Change) के नए मार्ग खोल दिए हैं, परंतु इसकी सीमाएँ भी स्पष्ट हैं। डिजिटल विभाजन (Digital Divide) के कारण ग्रामीण और वंचित वर्ग अभी भी इस माध्यम का समान रूप से उपयोग नहीं कर पाते, जिससे सामाजिक असमानता कहीं-न-कहीं बनी रहती है। इसके अलावा, सूचनाओं की प्रामाणिकता और तथ्यों की जांच न होने के कारण गलत जानकारी भी तीव्रता से फैल सकती है, जिससे सामाजिक भ्रम और ध्रुवीकरण (polarization) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः डिजिटल सक्रियता को एक प्रभावशाली सामाजिक उपकरण के रूप में स्वीकार करते हुए भी, इसके जटिल सामाजिक प्रभावों और सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

डिजिटल सक्रियता ने सामाजिक आंदोलनों और विचारों को फैलाने में अद्वितीय योगदान दिया है, लेकिन इसके साथ कई गंभीर चुनौतियाँ और सीमाएँ भी जुड़ी हुई हैं। पहली और सबसे प्रमुख चुनौती डिजिटल विभाजन (Digital Divide) है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में सूचना और तकनीकी संसाधनों के असमान वितरण के कारण उत्पन्न होती है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण, वहाँ के लोग इस प्रभावी मंच का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इस स्थिति के कारण, डिजिटल सक्रियता कुछ विशेष वर्गों तक सीमित रह जाती है, और समाज के अन्य हिस्सों तक इसका प्रभाव नहीं पहुँच पाता।

दूसरी प्रमुख सीमा सूचना की सत्यता और प्रामाणिकता (Authenticity and Veracity of Information) है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी जानकारी, अफवाहें, और प्रोपेगेंडा आसानी से फैल सकते हैं, जिससे आंदोलन या संदेश का वास्तविक उद्देश्य विकृत हो सकता है। कई बार बिना तथ्यों की पुष्टि किए हैशटैग्स और अभियानों के माध्यम से गलत सूचना का प्रसार होता है, जो समाज में भ्रम और आक्रोश का कारण बनता है। ऐसे मामलों में आंदोलन का संदेश कमजोर पड़ जाता है, और इसके सकारात्मक परिणामों की संभावना घट जाती है। इसके अतिरिक्त स्लैक्टिविज्म (Slacktivism), जिसे "ऑनलाइन सक्रियता" कहा जाता है, एक और महत्वपूर्ण सीमा है। यहाँ पर लोग डिजिटल मंचों पर आंदोलनों का समर्थन करने के बावजूद वास्तविक क्रियात्मक भागीदारी से दूर रहते हैं। यह प्रकार की सक्रियता एक प्रतीकात्मक कदम होता है, जिसमें लोग केवल हैशटैग्स का उपयोग करते हैं, पोस्ट लाइक करते हैं, और टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन कोई व्यावहारिक बदलाव लाने के लिए कार्य नहीं करते। इस प्रकार की डिजिटल सक्रियता से वास्तविक समाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में कोई ठोस योगदान नहीं होता।

एक अन्य समस्या सामाजिक ध्रुवीकरण (Social Polarization) का भी है। सोशल मीडिया पर विभिन्न विचारधाराएँ और समूह एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। लोग अपने-अपने नेटवर्कों में बंद होते जा रहे हैं और एक-दूसरे के विचारों को स्वीकारने के बजाय केवल अपने समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह समाज में विवाद और असहमति को और बढ़ावा देता है, जिससे संवाद और समझ में कमी आती है। अंत में, सुरक्षा और गोपनीयता (Security and Privacy) की चिंता भी एक गंभीर सीमा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाली सक्रियता व्यक्तिगत डेटा और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा से जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है। कई बार आंदोलनकारियों और समर्थकों को ऑनलाइन उत्पीड़न और शोषण का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा, सरकारें और अन्य शक्तिशाली संस्थाएँ सोशल मीडिया की निगरानी कर सकती हैं, जिससे आंदोलनों को दबाने और इसके प्रभाव को सीमित करने के प्रयास किए जा सकते हैं।

इस प्रकार, जबकि डिजिटल सक्रियता एक शक्तिशाली उपकरण साबित हुई है, इसकी चुनौतियाँ और सीमाएँ इसे एक पूर्ण समाधान नहीं बना पाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए तकनीकी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से समुचित उपायों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

डिजिटल सक्रियता ने भारतीय समाज में सामाजिक आंदोलनों को नया रूप दिया है और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसके प्रभाव को नकारा नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया ने आंदोलनों के संगठन, संदेश प्रसार और जनसमर्थन जुटाने की प्रक्रिया को तीव्र और प्रभावशाली बनाया है। इसके माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता, और मानवाधिकार जैसे मुद्दों को जन-जन तक पहुँचाना संभव हुआ है, जिससे समाज में जागरूकता और परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हुई है। हालांकि, डिजिटल सक्रियता के लाभों के साथ-साथ इसमें चुनौतियाँ और सीमाएँ भी हैं, जैसे कि डिजिटल विभाजन, गलत सूचना का प्रसार, स्लैक्टिविज्म, और सामाजिक ध्रुवीकरण। इन समस्याओं के बावजूद, सोशल मीडिया ने सत्ता और सूचना के केंद्रीकरण को चुनौती दी है और समाज में समानता और न्याय के लिए आवाज़ उठाने का एक नया मंच प्रदान किया है। भविष्य में, यदि इन सीमाओं और चुनौतियों पर ध्यान दिया जाए, तो डिजिटल सक्रियता को एक सशक्त और समावेशी सामाजिक उपकरण के रूप में और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है

कि तकनीकी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक सुरक्षित, प्रामाणिक, और सर्वजन हिताय बनाना जाए।

सन्दर्भ ग्रंथ:

1. Cavalcanti, D. B., Bringel, E. P. B., da Costa, F. R. J., de Oliveira, T. M., & Zuccolotto, V. R. (2019). Digital Activism and Indignation Nets in Brazil: The Pressure Groups. *Journal of Politics in Latin America*, 11(1), 109-130. <https://doi.org/10.1177/1866802X19840455> (Original work published 2019)
2. Airoldi M. (2018). Ethnography and the digital fields of social media. *International Journal of Social Research Methodology*, 21(6), 661-673. <https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1465622>
3. Blaagaard B. B., Roslyng M. M. (2022b). The spatial, networked and embodied agency of social media: A critical discourse perspective on Banksy's political expression. *Critical Discourse Studies*, 19(2), 212–226. <https://doi.org/10.1080/17405904.2020.1829665>
4. Pathak, Juhi. (2014). Digital Activism through social media; its applicability in creating political awareness in India. *Netaji Nagar Journal of English Literature and Language*. 2.
5. Mohammed, Hauwa. (2025). Women's Participation in Media and Social Justice Movement. *Journal of Informatics Education and Research*. 5. 10.52783/jier.v5i1.2288.

